>

Title: The Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries and Minister of State in the Ministry of Agriculture laid a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2012-13), pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): महोदया, मैं माननीय सभापति, राज्य सभा के निदेश के अनुसरण में स्थायी कृषि समिति की 33वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

स्थायी कृषि समिति की 33वीं रिपोर्ट संसद में दिनांक 26 अप्रैल, 2012 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2012-13 की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

उक्त 33वीं रिपोर्ट में समिति द्वारा 16 सिफारिशें/प्रेक्षण किए गए थे जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें अवसंरचना विकास, मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना, नए बूचड़खानों की स्थापना/मौजूदा बूचड़खानों की आधुनिकीकरण स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना एवं आधुनिकीकरण स्कीम, स्ट्रीट-फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम, गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान तथा विकास व अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम, संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम तथा नई स्कीमों से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा समिति को दी गई सूचना मेरे वक्तव्य के संलग्नक में दी गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैं संलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इसे पढ़ा गया समझा जाए।